import technology and metal from Japan. At least, 25 per cent railway projects have been tied to these procurement mandates. A rising Yen would increase the cost of imports and distort the trade balance further. India is net importer from Japan. The Government needs to have an action plan to deal with this challenge. I urge the Government to prepare plans to deal with the increase in interest rate by Bank of Japan that will have impacts on India's infrastructure projects.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Rajeev Shukla: Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala).

I urge the hon. Members, जो approved text है, ...

श्री राजीव शुक्ला: यह उसी से related है।

श्री उपसभापति: आपने जो कुछ चेंज किया है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री राजीव शुक्ला: सर, वह जाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As you know, only approved text can go. Now, Prof. Manoj Kumar Jha; not present. Next is Shrimati Sangeeta Yadav.

Demand for uniform curriculum across schools in India

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब देश के अधिकतर स्कूल CBSE, ICSE राज्य बोर्डों से संबद्धता और मान्यता प्राप्त हैं, तो यह सवाल उठता है कि इनके पाठ्यक्रम और किताबें क्यों अलग-अलग हैं? एक समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एकीकृत पाठ्यक्रम और पुस्तकों की आवश्यकता है। यह कदम न केवल छात्रों के शैक्षिक अनुभव को समान बनाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। पूरे देश में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुसंगत और समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

मैं आपके मध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए और स्कूलों द्वारा किसी एक प्रकाशक से किताबें खरीदने के लिए * बाध्य न किया जाए।

* Not recorded.

श्री उपसभापतिः जो approved text है, वही पढ़ें, कोई अतिरिक्त नया शब्द न पढ़ें, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्रीमती संगीता यादवः इसके लिए एक मानकीकरण नीति की आवश्यकता है, जो सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम और पुस्तकें लागू करे। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और राज्यों में SCERT जैसी संस्थाएं होती हैं, जिनके माध्यम से समान सिलेबस और किताबें लागू की जा सकती हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shrimati Sangeeta Yadav: Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Mahendra Bhatt (Uttarakhand), Shri Mayankbhai Jaydevbhai Nayak (Gujarat), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Krishan Lal Panwar (Haryana), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat) and Shri Kesridevsinh Jhala (Gujarat).

Concern over Kamakhyaguri Railway Flyover, Birpada Railway Flyover and Alipurduar Bara Bazar Flyover in West Bengal

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल): मैं आज कामाख्यागुड़ी रेलवे फ्लाईओवर, बीरपाड़ा रेलवे फ्लाईओवर और अलीपुरद्वार बड़ा बाजार फ्लाईओवर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सम्मानित सदन के ध्यान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है।

सबसे पहले, कामाख्यागुड़ी रेलवे फ्लाईओवर, कामाख्यागुड़ी और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस फ्लाईओवर की अधूरी स्थिति के कारण यातायात में भारी भीड़ पैदा हो गई है, जिससे यात्रियों को दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ, बीरपाड़ा रेलवे फ्लाईओवर एक कार्यात्मक फ्लाईओवर की अनुपस्थिति न केवल स्थानीय यातायात, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को भी बाधित करती है।

अंत में, अलीपुरद्वार बड़ा बाजार रेलवे फ्लाईओवर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, जो हलचल भरे बाजार क्षेत्र को जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति ने स्थानीय आबादी को गम्भीर ट्रैफिक जाम और सुरक्षा खतरों से जूझने पर मजबूर कर दिया है। इन फ्लाईओवर्स का पूरा होना सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए एक आवश्यकता है। मैं सरकार से इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, आवश्यक संसाधन आवंटित करने और उनके पूरा होने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने के लिए आपके माध्यम से आग्रह करता हूं।